## एक नजर में

### आलीराजपुर जिले को मिली बड़ी सौगात : करोड़ों की जल संसाधन परियोजनाएं स्वीकृत, सिंचाई और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

**आलीराजपुर।** जिले के विकास को नई दिशा देते हुए कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान एवं सांसद अनिता चौहान के सतत प्रयासों से जनसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा आलीराजपुर जिले को बड़ी सौगात प्रदान की गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे जिले में जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा और पर्यटन विकास को मजबूती मिलेगी। विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान एवं सांसद अनिता चौहान ने जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी को विभिन्न महत्वपूर्ण मांगो को लेकर पत्राचार करने के साथ दूरभाष पर चर्चा एवं प्रत्यक्ष में चर्चा कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया था। जिसके चलते जलसंसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट द्वारा ग्राम झंडाना स्थित हथनी-नर्मदा नदी संगम स्थल के तटों के संरक्षण एवं विकास के लिए 10 करोड़ 37 लाख 76 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत घाट निर्माण, तट सुरक्षा कार्य एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले इस स्थल का संरक्षण होगा, बल्कि पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

**आलीराजपुर एवं झाबुआ में बैराज स्वीकृत** -इसी के साथ कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान द्वारा की गई मांग पर जलसंसाधन विभाग द्वारा आलीराजपुर जिले में लघु सिंचाई परियोजनाओं के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बैराज निर्माण के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। उदयगढ़ क्षेत्र में बहेडिया बैराज के लिए 3करोड़ 84 लाख 77 हजार रुपए, सोंडवा क्षेत्र में तिकोला बैराज हेतु 20 करोड़ 14 लाख 17 हजार रुपए, ओझड़ बैराज के लिए 3 करोड़ 59 लाख 2 हजार रुपए तथा कट्ठीवाड़ा विकासखंड के फूलमाल क्षेत्र में बैराज निर्माण के लिए 3 करोड़ 49 लाख 70 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह झाबुआ जिले के भाजपा के कई जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद श्रीमती अनिता चौहान को पत्र सौंप कर बैराज की मांग की थी, जिसे सांसद श्रीमती अनिता चौहान ने जलसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को पत्र प्रेषित कर स्वीकृत करने का निवेदन किया था। जिसके चलते जलसमाधन मंत्री श्री सिलावट द्वारा झाबुआ जिले में राणापुर के खेड़ा गलती बैराज हेतु 4 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपए की स्वीकृति जारी की। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जल संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही सिंचाई का रकबा बढ़ने से किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है। विशेष रूप से आदिवासी बहुल इस जिले में इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष मकू परवाल, महामंत्री रिंकेश तंवर मोंटू शाह राजू मुवेल, जिला पंचायत अध्यक्ष हजरी बाई खरत, झाबुआ जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, जिला पंचायत सदस्य विजय भाबर सहित दोनों जिलों के कई जनप्रतिनिधियो, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का आभार व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान एवं सांसद अनिता चौहान को पहल करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

### आकाश के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

इंदौर. मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 के घोषित परिणामों में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के छात्रों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. इंदौर की छात्रा तन्वी कुमावत ने बायोलॉजी संकाय में 500 में से 492 अंक (98.40%) प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया. वहीं, अनुवंश सक्सेना ने 500 में से 482 अंक (96.40%) प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया. दोनों ही छात्र इंदौर स्थित आकाश इंस्टिट्यूट के गीता भवन सेंटर के विद्यार्थी है. इस उपलब्धि पर आकाश एजुकेशनल के चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड डॉ. एच. आर. राव ने कहा तन्वी और अनुवंश की उपलब्धि उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, साथ ही आकाश द्वारा दिए गए मजबूत शैक्षणिक माहौल और मार्गदर्शन को भी दर्शाती है.

### फोनपे से खरीद सकते हैं 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड

इंदौर. इस पावन अक्षय तृतीया पर अब सोना खरीदना पहले से भी आसान हो गया है। फोनपे के जरिए आप घर बैठे ही 99.99% शुद्ध 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से खरीद सकते हैं. फोनपे प्लेटफॉर्म पर आपको भरोसेमंद कंपनियों जैसे एमएमटीसी-पीएएमपी, सेफगोल्ड और कैरटलेन का गोल्ड मिलता है, जो पूरी तरह शुद्धता प्रमाणित होता है. इसकी खास सुविधा है कि गोल्ड की पेमेंट के कई विकल्प हैं जैसे यूपीआई, यूपीआई लाइट, कार्ड, वॉलेट, गिफ्ट कार्ड. इसके अलावा, एक बार में गोल्ड खरीद सकते हैं या रोजाना या मासिक एसआईपी के जरिए धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं, जिससे आप लंबे समय के लिए बचत कर सकते हैं. मात्र 10 रूपये से गोल्ड खरीदना शुरू सकते हैं. कभी भी अपना गोल्ड बेच सकते हैं.

### आईएजीईएस ने मप्र में की पकड़ मजबूत

इंदौर. मध्य प्रदेश के लोग अब बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि अब से सोना खरीदना हमेशा आसान और सुरक्षित रहेगा. जब बड़े और भरोसेमंद ज्वेलर्स को आईएजीईएस की मान्यता मिल चुकी है, तो अक्षय तृतीया या किसी भी शुभ दिन पर सोना खरीदना अब उनके लिए सबसे सुरक्षित और खुशी भरा अनुभव होगा. यह कहना है आईएजीईएस के सीईओ कौशलेंद्र सिन्हा का. इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चर्चा में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स (आईएजीईएस), जो सोने के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने वाला संगठन है, अपने ज्वेलर्स का नेटवर्क बढ़ा रहा है. इससे ग्राहकों को सोने की खरीदारी के लिए केवल सही और अच्छे विकल्प ही मिल पाएंगे. आईएजीईएस के पूरे देश में 550 से ज्यादा भरोसेमंद ज्वेलर्स के नेटवर्क में अब मध्य प्रदेश के कुछ बड़े ज्वेलर्स भी शामिल हैं. यह मानक दर्शाता है कि अब सोने की दुकानों में भरोसा, साफ-सुथरा काम और जिम्मेदारी बढ़ रही है. हमारी संस्कृति और आर्थिक नजर से सोने का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है, खासकर अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों में. लेकिन अब तक सोने का कारोबार काफी बिखरा हुआ था, जिससे लोगों को यह भरोसा नहीं रहता था कि दुकानों पर सब सही और पारदर्शी है. आईएजीईएस एक मजबूत मान्यता प्रणाली के जरिए इस समस्या को दूर करता है. आईएजीईएस पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रहा है- 'सोना खरीदने से पहले, पहला चेक आईएजीईएस'. इसके तहत लोगों को यह सलाह दी जाती है कि सोना खरीदने से पहले यह देख लें कि उनका सुनार आईएजीईएस से प्रमाणित है या नहीं.

### शाओमी टीवी एस मिनी एलईडी सीरीज लॉन्च

इंदौर. शाओमी इंडिया ने शाओमी टीवी एस मिनी एलईडी सीरीज़ के लॉन्च की घोषणा की. एडवांस्ड मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी पर बनी यह सीरीज़ स्क्रीन पर ज़्यादा कलर डेप्थ और क्लैरिटी लाती है, जिसमें ज़्यादा रिच कंट्रास्ट, संतुलित ब्राइटनेस और ज़्यादा डिटेल्ड विज़ुअल्स मिलते हैं. रंग जीवंत और असली जैसे दिखते हैं, जिसे इंटेलिजेंट कलर टेम्परेचर ट्यूनिंग का सपोर्ट मिलता है. अनुज शर्मा, चीफ़ मार्केटिंग ऑफ़िसर, शाओमी इंडिया ने कहा कि शाओमी मिनी एलईडी टीवी के साथ, हमारा फ़ोकस इस बात पर है कि डिस्प्ले बुनियादी स्तर पर कैसा परफ़ॉर्म करता है. हमारी टेक्नोलॉजी बैकलाइटिंग पर ज़्यादा सटीक कंट्रोल देती है, जिससे पूरे पैनल में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है. इसका नतीजा यह होता है कि काले रंग ज़्यादा गहरे, हाइलाइट्स ज़्यादा

# अवैध रेत का कारोबार जोरों पर, बेरोकटोक दौड़ रहे ओवरलोड रेत के डंपर

▶ लोगों को अब नवागत कलेक्टर से हैं कार्रवाई की उम्मीद

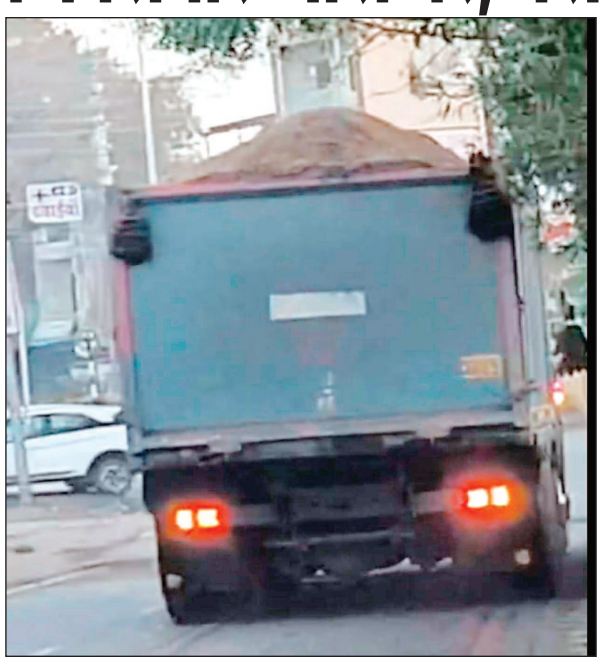

**पेटलावद।** कुछ माह पूर्व ही रेत पर चलने वाले डंपर द्वारा जिला कलेक्टर नेहा मीना के वाहन को टक्कर मार दी गई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर एक्शन में दिखाई दीं और जिला खनिज विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई रेत के कारोबारियों पर देखने को मिली।

जिले में कई जगहों पर अवैध रेत से भरे डंपर खनिज विभाग ने पकड़ कर लाखों की पेनल्टी वसूल की थी, जिस प्रकार से जिले भर में अवैध रेत के कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिससे लग रहा था कि अवैध रेत के इस काले धंधे पर रोक लगेगी। जिले से शुरू हुई कार्यवाही कुछ ही दिनों की मेहमान रही ओर अवैध रेत का कारोबार इन दिनों फिर से अपने पूरे चरम पर है। आलम ये है कि रेत ओवर लोड भरे डंफर बेधड़क नगर की सड़को पर दौड़ने लग गए जिनको रोकने वाला कोई नहीं है।

**नगर में रोज आ रहे 15 से 20 डंपर** -अवैध रूप से नगर में चारों ओर रेत का कारोबार किया जा रहा है, यहां एक दो नहीं रोज के लगभग 15 से 20 डंफर रेत आती हैं। जिसमें से लगभग डंफर ओवर लोड होते है क्योंकि अंडर लोड डंफर लाना मतलब डंफर मालिक को किसी प्रकार का मुनाफा नहीं मिल पाता, सूत्रों की माने तो कई वाहनों के पास रॉयल्टी की रसीद तक नहीं होती तो कई वाहन एक ही रसीद पर आ जाते है। स्थानीय स्तर पर मौजूद दलाल नगर में आए इन डंफर को कमीशन पर ठिकाने लगाते हैं।

> गुजरात और आलीराजपुर जिले से रेत भर के ये वाहन दो, तीन ओर चार जिले पार कर निकल जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, कहने को तो खनिज विभाग का अमला मौजूद है लेकिन रेत के डंफर देख कर ही विभाग दुबक जाता है, आलम ये है कि कई मीडिया में आई खबरों के बाद भी खनिज विभाग की कोई बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिलती हैं। स्थानीय स्तर के अधिकारी भी रेत के इस अवैध कारोबार को देखा अनदेखा कर देते है। जिससे ये स्पष्ट लगता है कि पूरा कारोबार मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अब इस मिलीभगत की बंदरबाट में कौन कौन शामिल हैं इसकी जानकारी रेत सप्लाई में लगे दलालों के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता लग जाएगी। इस काले कारोबार के पीछे कौन कौन से विभाग के जिम्मेदार शामिल है।
>
> **कार्रवाई होगी तो रुकेगी टैक्स चोरी** -जिस तरह से अवैध रेत के मामले में कार्यवाही कलेक्टर नेहा मीना ने शुरू की थी उसी प्रकार की कार्यवाही को फिर शुरू करना होग। जिसकी उम्मीद नवागत जिला कलेक्टर से है ताकि रोज होने वाली राजस्व चोरी पर रोक लग पाए।

### साफ्टेल लाया- पारंपरिक पिसाई की नई पहचान

इंदौर. साफ्टेल, आधुनिक घरों के लिए पिसाई का एक नया तरीका लेकर आ रहा है. इसकी कॉम्पैक्ट घरघंटी ताज़ा पीसने को फिर से आसान बनाती है. यह इतनी छोटी है कि रसोई के प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से रखी जा सकती है और इतनी शक्तिशाली है कि अनाज, बाजरा और मसाले आसानी से पीस सकती है. घरघंटी के मूल में पत्थर-आधारित पीसने की प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक स्वाद, बनावट और पोषण को बनाए रखने में मदद करती है. साफ्टेल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार जैन कहते हैं ताज़ा भोजन कोई विलासिता नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार है. रोज़ ताज़ा पीसना हमारे भोजन में शुद्धता, पोषण और विश्वास वापस लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है. इस लॉन्च के साथ साफ्टेल सिर्फ एक उत्पाद पेश नहीं कर रहा है, बल्कि ताज़ा और ईमानदार भोजन को फिर से रोज़मर्रा की आदत बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है.

# कलेक्टर-सीईओ जिला पंचायत ने बावड़ी सफाई में किया श्रमदान

▶ अभियान को मिशन मोड में लेकर कार्य को गति से किया जाए- कलेक्टर माथुर

**आलीराजपुर।** मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के समस्त जिलों में जल संचय, जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे है। इसका उद्देश्य प्रदेश की जल संरचनाओं का संरक्षण, संवर्धन करना है। इसी के परिपालन में जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान का सुचारू संचालन किया जा रहा है।

कलेक्टर नीतू माथुर एवं जिला पंचायत सीईओ संघमित्रा गौतम द्वारा जनपद पंचायत आलीराजपुर के ग्राम चौंगनवाट में स्थित प्राचीन बावड़ी की साफ-सफाई, बावड़ी से गाद निकासी का कार्य श्रमदान कर किया गया। इस दौरान उपस्थित समस्त जन ने जल संरचनाओं की साफ सफाई ,उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कलेक्टर नीतू माथुर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिसका हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर कार्य करना चाहिए। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जल संरचनाओं का संरक्षण कर भूमिगत जल स्तर में सुधार करना है।

बावड़ी सफाई के उपरांत कलेक्टर माथुर एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती गौतम की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में समस्त जनपद सीईओ की जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक ली गई जिसमें कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने समस्त जनपद सीईओ को अभियान को मिशन मोड में लेकर जल संरक्षण के कार्यों में गति लाने, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान,एसीईओ,जनपद सीईओ आलीराजपुर सहित स्थानीय नागरिक, सरपंच, सचिव मौजूद रहे।

## नगर पालिका सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा राजस्व अधिकारी खान को

**आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर राजस्व अधिकारी मामून ख़ान को उनके वर्तमान प्रभार क्षेत्र के साथ-साथ नगरपालिका परिषद आलीराजपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।**

खान ने शनिवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने तकनीकी एवं कार्यालयीन स्टाफ की बैठक ली और कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने, आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने तथा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतोषजनक निराकरण कर उन्हें स्वेच्छा से बंद कराने पर भी जोर दिया।कलेक्टर के निर्देशानुसार श्री खान ने कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम की सुचारु व्यवस्था के लिए कर्मचारियों के बीच कार्यों का विभाजन किया।उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम में कुल 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

# घर के पास मिली स्वास्थ्य सुविधा, मोबाइल यूनिट ने संभाली गर्भवती संध्या की जिम्मेदारी

▶ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही गांव की चौखट तक

**आलीराजपुर।** दूर-दराज गांवों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा एक चुनौती रहती हैं। लेकिन अब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चल रही मेडिकल मोबाइल यूनिट इन चुनौतियों को आसान बना रही है। इसका एक सजीव उदाहरण है ग्राम कुंडलवासा की संध्या का। वह बताती है कि वह गर्भवती हैं और उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी समय पर जांच कैसे कराएं? गांव से अस्पताल दूर होने तथा आने-जाने का साधन नहीं होने और हर बार जांच छूट जाने का डर रहता था। जिससे वह अपने गर्भावस्था को लेकर चिंतित रहती थी। लेकिन तभी उन्हें गांव में मेडिकल मोबाइल यूनिट पहुंचने की जानकारी मिली जो कि हर तय दिन पर डॉक्टरों की टीम के साथ गांव आती है। संध्या ने मेडिकल मोबाइल यूनिट से सभी जरूरी जांचें कराई। अब उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

संध्या बताती है कि मोबाइल यूनिट में आने वाली टीम डॉ. अंकित ठाकुर द्वारा नियमित रूप से उनकी जांच की जा रही है।

> उनकी हर विजिट में वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, शुगर और यूरिन जैसी जरूरी जांचें की जाती हैं। साथ ही टिटनेस का टीका, आयरन और कैल्शियम की दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। डॉक्टर पोषण और साफ-सफाई को लेकर भी सलाह देते हैं। घर के पास ही सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर संध्या खुश होकर कहती हैं कि पहले बहुत चिंता होती थी कि अस्पताल कैसे जाऊंगी, लेकिन अब गाड़ी गांव आ जाती है। डॉक्टर यहीं जांच कर लेते हैं और दवाइयां भी मिल जाती हैं। अब मैं निश्चिंत हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव की अन्य महिलाएं भी इस सुविधा से जुड़ रही हैं। अब उन्हें गर्भावस्था के दौरान जांच छूटने का डर नहीं रहता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं अब गांव की चौखट तक पहुंच रही हैं। इससे न सिर्फ मातृ-शिशु स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। संध्या ने शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के लिए आभार व्यक्त किया और गांव की अन्य महिलाओं को भी इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उक्त सफलता की कहानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई।

## एक नजर में ▶ मध्य प्रदेश में 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध

# डिजिटल तकनीक आज सुशासन की बन चुकी है आधारशिला...

**आलीराजपुर।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप' के माध्यम से प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त आधार मिला है। इससे नागरिक सेवाएं अब अधिक सरल, सुगम और सुलभ हुई हैं। डिजिटल तकनीक आज सुशासन की आधारशिला बन चुकी है और प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान स्थापित कर रहा है।

अब प्रदेशवासियों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही मंच पर सभी सुविधाएँ सहज, त्वरित और पारदर्शी रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनी है। साथ ही नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म नागरिकों, विभागों एवं सेवाओं को एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम में जोड़ते हुए सुशासन को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

**एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएं प्रक्रिया हुई सरल:** एमपी ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बार-बार अलग-अलग पोर्टल पर जाने और दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता समाप्त की गई है। नागरिक अब मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है।

**समग्र पोर्टल से एकीकरण ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा :** 'एमपी ई-सेवा' को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8 अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9 अंकीय सदस्य आईडी दी गई है। इससे ऑटो-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया है। इससे पात्रता निर्धारण स्वत: हो जाता है और अनावश्यक देरी व दोहराव समाप्त होता है। पोर्टल की प्रमुख विशेषता 'ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स' है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहती।एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज आगे की सेवाओं में स्वत: उपलब्ध हो जाते हैं।

> **सुगम, सुरक्षित एवं नागरिक केंद्रित 'ऐप-डिज़ाइन'**
>
> एमपी ई-सेवा पोर्टल को मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है। इसमें बहुभाषीय सुविधा के साथ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष डिज़ाइन किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सकें। प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख 14 हजार से अधिक ट्रांसेक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 3 हजार 446 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 1 लाख 64 हजार 600 से अधिक ट्रैक/डाउनलोड गतिविधियाँ और 45 हजार 954 समग्र पात्रता जांचें की गई हैं।
>
> **डिजिटल गवर्नेंस में प्रदेश की सशक्त उपस्थिति**-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) 2025 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप कर सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को 100 प्रतिशत एकीकृत करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्रदेश को 'सायबर तहसील' के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार तथा 'संपदा 2.0' के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को दर्शाते हैं।